दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती हुई भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रो. गोपाल प्रसाद[1], विकास कुमार पाण्डेय[2]

[1] वरिष्ठ आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

सार

इक्कीसवीं सदी में वैश्विक शक्ति-संतुलन के परिवर्तन ने दक्षिण एशिया को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सामरिक एवं भू-राजनीतिक क्षेत्र बना दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में चीन ने वर्ष 2013 में प्रारम्भ की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव तथा अन्य दक्षिण एशियाई देशों में अवसंरचनात्मक विकास, ऊर्जा, परिवहन, बंदरगाह और डिजिटल संपर्क परियोजनाओं में व्यापक निवेश कर अपनी आर्थिक एवं रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ किया है। इसके समानांतर भारत ने नेबरहुड फर्स्ट, सागर (SAGAR), महासागर (MAHASAGAR) तथा क्वाड (QUAD) जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन एवं सामरिक सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। यह अध्ययन गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति पर आधारित है तथा समकालीन साहित्य, सरकारी दस्तावेजों, थिंक-टैंक रिपोर्टों और 2025–2026 तक की प्रमुख घटनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि चीन की बढ़ती भूमिका दक्षिण एशिया के लिए एक ओर आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क और निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराती है, वहीं दूसरी ओर ऋण निर्भरता, सामरिक अवसंरचना, डिजिटल प्रभाव तथा क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन से संबंधित नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती है। निष्कर्षतः, दक्षिण एशियाई देश किसी एक महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय सामरिक स्वायत्तता एवं बहु-संरेखण (Multi-alignment) की नीति को प्राथमिकता देते हुए बदलते क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन के अनुरूप अपनी विदेश नीति का पुनर्संयोजन कर रहे हैं।

मुख्य शब्द: दक्षिण एशिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऋण कूटनीति, भारत-चीन संबंध, हिंद महासागर, क्षेत्रीय सुरक्षा।

1. प्रस्तावना

दक्षिण एशिया समकालीन विश्व राजनीति का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आर्थिक विकास, सामरिक प्रतिस्पर्धा तथा भू-राजनीतिक हित एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान तथा अफ़ग़ानिस्तान से मिलकर बना यह क्षेत्र न केवल विश्व की लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या का निवास स्थान है, बल्कि हिंद महासागर के माध्यम से वैश्विक व्यापार, ऊर्जा परिवहन तथा समुद्री संपर्क का भी प्रमुख केंद्र है। पश्चिम एशिया से पूर्वी एशिया तक जाने वाले अधिकांश ऊर्जा मार्ग इसी समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण दक्षिण एशिया का सामरिक महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है (CKGSB Knowledge, 2026)। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हुए परिवर्तनों ने चीन को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख आर्थिक एवं सामरिक शक्ति के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया। तीव्र आर्थिक विकास, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार तथा औद्योगिक क्षमता के आधार पर चीन ने अपनी विदेश नीति को केवल व्यापार तक सीमित न रखते हुए वैश्विक संपर्क, निवेश तथा अवसंरचना निर्माण पर आधारित रणनीति विकसित की। वर्ष 2013 में राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा घोषित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) इसी व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम था। इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका को सड़क, रेल, समुद्री मार्ग, ऊर्जा गलियारों तथा डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना था। वर्ष 2025 तक BRI में लगभग 150 देश किसी न किसी रूप

में सहभागी बन चुके थे तथा इसकी संचयी निवेश प्रतिबद्धता लगभग 1.39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई थी (Griffith Asia Institute, 2026)।

दक्षिण एशिया चीन की इस रणनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यह चीन को हिंद महासागर तक वैकल्पिक पहुँच उपलब्ध कराता है, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा समुद्री व्यापारिक मार्गों पर उसकी निर्भरता को अधिक संतुलित बनाता है। पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह, नेपाल की सीमा-पार रेल परियोजनाएँ, बांग्लादेश के बंदरगाह एवं औद्योगिक निवेश तथा मालदीव की समुद्री अवसंरचना परियोजनाएँ चीन की इसी व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा हैं (CPEC Secretariat, 2026; CSIS, 2026)।

हालाँकि चीन की बढ़ती भूमिका को लेकर विद्वानों के मध्य मतभेद भी विद्यमान हैं। एक पक्ष का मत है कि चीन विकासशील देशों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान कर रहा है। इसके विपरीत दूसरा पक्ष इसे ऋण-आधारित निर्भरता, सामरिक प्रभाव विस्तार तथा राजनीतिक दबाव का माध्यम मानता है। विशेष रूप से श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह, पाकिस्तान के बढ़ते ऋण तथा मालदीव की वित्तीय निर्भरता को लेकर "ऋण-जाल कूटनीति" (Debt Trap Diplomacy) की अवधारणा व्यापक बहस का विषय बनी हुई है। हालांकि हाल के अनेक अध्ययनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रीलंका का आर्थिक संकट केवल चीनी ऋण का परिणाम नहीं था, बल्कि घरेलू आर्थिक नीतियाँ, अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों से लिए गए ऋण तथा विदेशी मुद्रा संकट भी इसके प्रमुख कारण थे (Georgetown Journal of International Affairs, 2021; Friends of Socialist China, 2026; CSIS, 2026)। वर्ष 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों में उत्पन्न तनाव ने दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति को और अधिक जटिल बना दिया। सीमा विवादों के साथ-साथ हिंद महासागर, डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों के संबंधों को बहुआयामी बना दिया है। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट, सागर, महासागर, क्वाड, इंडो-पैसिफिक महासागरीय डोमेन जागरूकता (IPMDA) तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसी पहलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है (KSPP, 2026; StudyIQ, 2026; ORF, 2026)। वर्तमान समय में चीन की दक्षिण एशिया नीति पारंपरिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं से आगे बढ़कर डिजिटल सिल्क रोड, हरित ऊर्जा, 5G संचार नेटवर्क, स्मार्ट बंदरगाह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला तथा डिजिटल वित्तीय सहयोग जैसे नए क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुकी है। इससे दक्षिण एशिया की भू-राजनीति केवल पारंपरिक सैन्य प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं रही, बल्कि तकनीकी, आर्थिक तथा समुद्री शक्ति के नए आयामों से भी जुड़ गई है।

इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध-पत्र दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका का आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक तथा भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि चीन की क्षेत्रीय रणनीति ने दक्षिण एशिया के शक्ति-संतुलन, भारत की विदेश नीति तथा क्षेत्रीय देशों की सामरिक स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित किया है। साथ ही यह शोध वर्तमान समकालीन घटनाओं के आलोक में भविष्य की संभावित क्षेत्रीय दिशा का भी मूल्यांकन करता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में चीन की निरंतर बढ़ती आर्थिक, सामरिक तथा कूटनीतिक भूमिका का समकालीन परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना है। विशेष रूप से यह अध्ययन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं, क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन, भारत–चीन प्रतिस्पर्धा तथा दक्षिण एशियाई देशों की विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करता है। चीन की बढ़ती सक्रियता ने दक्षिण एशिया की पारंपरिक भू-राजनीतिक संरचना में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिनका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. दक्षिण एशियाई देशों में चीन की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक भूमिका का विश्लेषण करना।
2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) तथा चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के क्षेत्रीय प्रभावों का मूल्यांकन करना।
3. चीन की तथाकथित ऋण कूटनीति (Debt Diplomacy) तथा उसके पक्ष एवं विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों का आलोचनात्मक अध्ययन करना।
4. भारत–चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा तथा हिंद महासागर क्षेत्र में उभरते सुरक्षा आयामों का विश्लेषण करना।
5. दक्षिण एशियाई देशों द्वारा अपनाई जा रही सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) तथा संतुलनकारी विदेश नीति का अध्ययन करना।
6. वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीतिक दिशा का मूल्यांकन करना।

3. शोध प्रविधि

यह शोध गुणात्मक (Qualitative) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्र, प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाएँ, सरकारी दस्तावेज, नीति-पत्र, थिंक-टैंक रिपोर्टें तथा विश्वसनीय समाचार स्रोतों का समावेश किया गया है। विशेष रूप से Observer Research Foundation (ORF), CSIS, MP-IDSA, Griffith Asia Institute, ISAS-NUS, The Diplomat, Reuters, Al Jazeera, तथा विभिन्न सरकारी वेबसाइटों से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया गया है।

शोध में तुलनात्मक (Comparative) एवं वर्णनात्मक (Descriptive) विश्लेषण का भी उपयोग किया गया है, जिससे विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों में चीन की नीतियों की प्रकृति, उद्देश्य तथा परिणामों की तुलना की जा सके। अध्ययन में 2025–2026 तक के समकालीन घटनाक्रमों को भी सम्मिलित किया गया है ताकि बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों का अद्यतन मूल्यांकन प्रस्तुत किया जा सके।

4. सैद्धान्तिक आधार

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका को समझने के लिए केवल आर्थिक विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सिद्धांतों का समन्वित उपयोग आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः यथार्थवाद (Realism), आक्रामक यथार्थवाद (Offensive Realism), जियो-इकोनॉमिक्स (Geoeconomics) तथा जटिल पारस्परिक निर्भरता (Complex Interdependence) के दृष्टिकोणों पर आधारित है।

4.1 आक्रामक यथार्थवाद

जॉन जे. मियरशाइमर के आक्रामक यथार्थवाद के अनुसार प्रत्येक महाशक्ति अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व का विस्तार करने का प्रयास करती है ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस दृष्टिकोण से चीन का दक्षिण एशिया में निवेश केवल आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि वह अपने दीर्घकालिक सामरिक हितों की रक्षा हेतु क्षेत्रीय प्रभाव स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान, श्रीलंका तथा हिंद महासागर के बंदरगाहों में चीन की बढ़ती उपस्थिति इसी रणनीतिक सोच को प्रतिबिंबित करती है (Mearsheimer, 2001)।

4.2 जियो-इकोनॉमिक्स

एडवर्ड लुटवाक द्वारा प्रतिपादित जियो-इकोनॉमिक्स की अवधारणा के अनुसार आधुनिक विश्व में आर्थिक साधनों का उपयोग सामरिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चीन की BRI परियोजनाएँ, विकास ऋण, औद्योगिक पार्क,

ऊर्जा गलियारे तथा डिजिटल अवसंरचना इस रणनीति के प्रमुख उदाहरण हैं। आर्थिक निवेश के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव तथा रणनीतिक पहुँच प्राप्त करना चीन की विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण आयाम बन चुका है (Luttwak, 1990)।

4.3 जटिल पारस्परिक निर्भरता : रॉबर्ट कीओहैन और जोसेफ नाए के अनुसार आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं हैं, बल्कि व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सहयोग भी राज्यों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। चीन और दक्षिण एशिया के मध्य बढ़ते व्यापारिक संबंध इसी सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। अनेक दक्षिण एशियाई देश चीन के साथ आर्थिक सहयोग को जारी रखते हुए भारत, अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय देशों के साथ भी अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं, जिससे संतुलित विदेश नीति का विकास हो रहा है (Keohane & Nye, 1977)।

5. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI): चीन की वैश्विक एवं क्षेत्रीय रणनीति

वर्ष 2013 में राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा घोषित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) चीन की अब तक की सबसे महत्त्वाकांक्षी वैश्विक अवसंरचना एवं संपर्क परियोजना है। इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के देशों को सड़क, रेल, समुद्री मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन, डिजिटल नेटवर्क तथा औद्योगिक गलियारों के माध्यम से जोड़ना है। समय के साथ BRI केवल अवसंरचना कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह चीन की विदेश नीति, वैश्विक आर्थिक कूटनीति तथा भू-राजनीतिक रणनीति का केंद्रीय आधार बन गया है (Ammu & Ajitha, 2026)।

Griffith Asia Institute (2026) के अनुसार वर्ष 2025 तक BRI के अंतर्गत संचयी निवेश एवं निर्माण अनुबंध लगभग 1.39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुके थे। केवल वर्ष 2025 में ही लगभग 213.5 अरब अमेरिकी डॉलर के नए निवेश एवं निर्माण समझौते हुए, जो इस पहल के आरंभ के बाद का सर्वाधिक वार्षिक स्तर था। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चीन ने BRI को अपनी विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बनाए रखा है (Griffith Asia Institute, 2026)।

दक्षिण एशिया BRI का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह चीन को हिंद महासागर तक वैकल्पिक समुद्री पहुँच प्रदान करता है। चीन के लिए मलक्का दुविधा (Malacca Dilemma) लंबे समय से एक प्रमुख सामरिक चुनौती रही है। चीन के अधिकांश ऊर्जा आयात मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरते हैं, जहाँ किसी भी भू-राजनीतिक संकट की स्थिति में उसकी ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी कारण पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, म्यांमार के क्याउकफ्यू बंदरगाह तथा श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को चीन अपनी समुद्री रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में विकसित कर रहा है (KSPP, 2026)।

6. दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका: देशवार विश्लेषण

6.1 पाकिस्तान : चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और सामरिक साझेदारी

दक्षिण एशिया में चीन की विदेश नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार पाकिस्तान है। दोनों देशों के संबंध समय के साथ पारंपरिक कूटनीतिक सहयोग से आगे बढ़कर व्यापक सामरिक, आर्थिक तथा तकनीकी साझेदारी में परिवर्तित हो चुके हैं। चीन पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा, हिंद महासागर तक प्रत्यक्ष पहुँच, ऊर्जा सुरक्षा तथा भारत के विरुद्ध सामरिक संतुलन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। दूसरी ओर पाकिस्तान चीन को अपनी आर्थिक चुनौतियों के समाधान, अवसंरचनात्मक विकास तथा रक्षा आधुनिकीकरण के प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार करता है (East Asia Forum, 2025)। चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China–Pakistan Economic Corridor—CPEC), जिसकी घोषणा वर्ष 2015 में हुई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख (Flagship) परियोजना मानी जाती है। लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा यह गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल सड़क एवं रेल संपर्क विकसित करना नहीं है, बल्कि

ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs), डिजिटल कनेक्टिविटी तथा बंदरगाह विकास के माध्यम से व्यापक आर्थिक परिवर्तन लाना भी है (CPEC Secretariat, 2026)।

उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार CPEC के अंतर्गत अब तक 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश किया जा चुका है, जिससे लगभग 8,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित हुई तथा दो लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए (CPEC Secretariat, 2026)। जनवरी 2025 में ग्वादर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन प्रारम्भ होना तथा ग्वादर अस्पताल, जलापूर्ति परियोजनाओं एवं ऊर्जा अवसंरचना का विस्तार इस सहयोग की नवीन उपलब्धियाँ हैं।

6.2 श्रीलंका : हंबनटोटा बंदरगाह, ऋण कूटनीति और सामरिक बहस

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका का सबसे चर्चित उदाहरण श्रीलंका है। हिंद महासागर के मध्य स्थित होने के कारण श्रीलंका लंबे समय से वैश्विक समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। चीन ने इसी सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका में बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक निवेश किया, जिनमें हंबनटोटा बंदरगाह, कोलंबो पोर्ट सिटी, एक्सप्रेसवे तथा ऊर्जा परियोजनाएँ प्रमुख हैं (The Diplomat, 2025)। हंबनटोटा बंदरगाह को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "ऋण-जाल कूटनीति" (Debt Trap Diplomacy) की अवधारणा व्यापक चर्चा का विषय बनी। वर्ष 2017 में श्रीलंका ने इस बंदरगाह को 99 वर्षों की लीज़ पर China Merchants Port Holdings को सौंप दिया, जिसके बाद अनेक पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे चीन की रणनीतिक सफलता के रूप में प्रस्तुत किया (CSIS, 2026)।इस प्रकार श्रीलंका का अनुभव यह दर्शाता है कि चीन का निवेश आर्थिक अवसर तो प्रदान करता है, किन्तु उसके साथ सामरिक संवेदनशीलता तथा विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी जुड़ी रहती है।

6.3 नेपाल : आर्थिक सहयोग, रणनीतिक संतुलन और BRI का नया चरण

नेपाल दक्षिण एशिया का ऐसा देश है जहाँ भारत और चीन दोनों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रभाव विद्यमान है। भौगोलिक रूप से हिमालयी क्षेत्र में स्थित नेपाल चीन के लिए तिब्बत से जुड़ने तथा दक्षिण एशिया तक पहुँच का महत्वपूर्ण माध्यम है, जबकि भारत के लिए यह पारंपरिक सुरक्षा एवं सांस्कृतिक साझेदारी का अभिन्न अंग रहा है।

नेपाल ने वर्ष 2017 में BRI पर हस्ताक्षर किए, किन्तु कई वर्षों तक अधिकांश परियोजनाएँ प्रारम्भ नहीं हो सकीं। दिसंबर 2024 में नेपाल और चीन के मध्य BRI Cooperation Framework पर सहमति बनने के बाद सीमा-पार रेल संपर्क, सड़क निर्माण, ऊर्जा सहयोग तथा डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को नई गति मिली (Rising Nepal Daily, 2025; Vivekananda International Foundation, 2026)।

वर्ष 2025–2026 में चीन ने नेपाल में परिवहन, जलविद्युत, सीमा व्यापार तथा डिजिटल अवसंरचना में निवेश बढ़ाने की रणनीति अपनाई। इसके साथ ही पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की चर्चा ने BRI परियोजनाओं की पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर भी प्रश्न खड़े किए (The Borderlens, 2025)। नेपाल की विदेश नीति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसका संतुलनकारी दृष्टिकोण है। एक ओर वह चीन के निवेश और अवसंरचना सहयोग का लाभ उठाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारत के साथ अपने ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों को भी बनाए रखना चाहता है। इसलिए नेपाल की रणनीति को "Strategic Balancing" या "Hedging Strategy" के रूप में देखा जाता है (South Asian Voices, 2025)।

6.4 बांग्लादेश : आर्थिक साझेदारी से सामरिक पुनर्संतुलन तक: दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका का एक महत्वपूर्ण आयाम बांग्लादेश के साथ उसके गहरे होते आर्थिक एवं सामरिक संबंध हैं। पिछले डेढ़ दशक में चीन ने बांग्लादेश को केवल व्यापारिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपनी

दीर्घकालिक रणनीति के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित किया है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति, तीव्र आर्थिक विकास, समुद्री तट तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के मध्य स्थित होने के कारण चीन की इंडो-पैसिफिक रणनीति में उसका विशेष स्थान है (ORF, 2026)। बांग्लादेश वर्ष 2016 में आधिकारिक रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में सम्मिलित हुआ। इसके पश्चात चीन ने सड़क, रेलवे, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्रों, पुलों तथा बंदरगाहों सहित अनेक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निवेश किया। वर्तमान में चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रमुख स्रोतों में भी शामिल है। वर्ष 2025 तक दोनों देशों के मध्य लगभग 42 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की विभिन्न निवेश एवं विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा था (ISAS-NUS, 2026; ORF, 2026)।

अगस्त 2024 में बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों में आए परिवर्तन के बाद चीन ने नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने संबंधों को और अधिक सक्रिय बनाया। मार्च 2025 में बीजिंग यात्रा के दौरान बांग्लादेश को लगभग 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर के नए निवेश एवं वित्तीय सहयोग की घोषणा की गई। मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण, औद्योगिक पार्कों, ऊर्जा परियोजनाओं तथा डिजिटल अवसंरचना में चीन की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी (Fair Observer, 2025)। आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त चीन बांग्लादेश के रक्षा आधुनिकीकरण का भी प्रमुख साझेदार बन चुका है। बांग्लादेश की नौसेना, वायुसेना तथा थलसेना के आधुनिकीकरण में चीनी रक्षा उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। युद्धपोत, लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली तथा बख़्तरबंद वाहनों की आपूर्ति ने दोनों देशों के सामरिक संबंधों को नई दिशा प्रदान की है। वर्ष 2026 में चीन द्वारा VT-5 हल्के टैंकों की अतिरिक्त आपूर्ति इस सहयोग की निरंतरता को दर्शाती है (Eurasia Review, 2025)। हालाँकि बांग्लादेश ने चीन के साथ अपने संबंधों का विस्तार किया है, फिर भी उसने भारत के साथ आर्थिक, ऊर्जा तथा सुरक्षा सहयोग को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। यही कारण है कि बांग्लादेश वर्तमान में संतुलित विदेश नीति (Balanced Foreign Policy) अपनाते हुए भारत, चीन, जापान, अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के साथ समानांतर सहयोग बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशियाई देशों की विदेश नीति अब एकध्रुवीय निर्भरता के बजाय बहुध्रुवीय संतुलन की दिशा में विकसित हो रही है (ORF, 2026)।

6.5 मालदीव : हिंद महासागर में सामरिक प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र: मालदीव, यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, किंतु हिंद महासागर के समुद्री मार्गों के मध्य स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व अत्यंत अधिक है। पश्चिम एशिया से पूर्वी एशिया तक जाने वाले प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग मालदीव के निकट से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि भारत और चीन दोनों इस क्षेत्र को अपनी समुद्री सुरक्षा एवं क्षेत्रीय रणनीति का महत्त्वपूर्ण भाग मानते हैं (ORCA, 2022)। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने के पश्चात मालदीव की विदेश नीति में चीन की ओर स्पष्ट झुकाव देखा गया। "India Out" अभियान के राजनीतिक प्रभाव तथा चीन के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग ने क्षेत्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दिया। जनवरी 2025 से लागू चीन–मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया (ORF, 2025)।

6.6 अफ़ग़ानिस्तान : संसाधन, संपर्क और रणनीतिक संभावनाएँ

अफ़ग़ानिस्तान लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा चुनौतियों तथा आर्थिक संकट का सामना करता रहा है। इसके बावजूद चीन ने इस देश को मध्य एशिया, दक्षिण एशिया तथा पश्चिम एशिया के मध्य संपर्क स्थापित करने वाले महत्त्वपूर्ण भू-भाग के रूप में देखा है। विशेष रूप से तांबा, लिथियम तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों ने चीन की रुचि को और अधिक बढ़ाया है (CKGSB Knowledge, 2026)। वर्ष 2025 में चीन, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के मध्य त्रिपक्षीय वार्ताओं में CPEC को अफ़ग़ानिस्तान तक विस्तारित करने की संभावना पर चर्चा हुई। यदि भविष्य में यह परियोजना पूर्ण होती है तो मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया के मध्य व्यापारिक संपर्क को नई दिशा मिल सकती है (Al Jazeera, 2026)। हालाँकि अफ़ग़ानिस्तान की राजनीतिक अनिश्चितता, आतंकवादी गतिविधियाँ, निवेश सुरक्षा तथा

अंतरराष्ट्रीय मान्यता से जुड़े प्रश्न अभी भी चीन की दीर्घकालिक रणनीति के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ बने हुए हैं। इसलिए चीन वर्तमान में सीमित लेकिन सतर्क आर्थिक भागीदारी की नीति अपनाता दिखाई देता है।

7. भारत–चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा : बदलता क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव भारत–चीन संबंधों पर पड़ा है। दोनों देश एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और सैन्य शक्तियों में शामिल हैं। परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया, हिंद महासागर तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों के हित कई स्थानों पर परस्पर प्रतिस्पर्धी दिखाई देते हैं। वर्ष 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंधों में गहरा अविश्वास उत्पन्न हुआ। यद्यपि उसके बाद कई दौर की सैन्य एवं राजनयिक वार्ताएँ आयोजित हुईं और 2024–2026 के दौरान कुछ क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर सहमति बनी, फिर भी सीमा विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है (StudyIQ, 2026)। सीमा विवादों के अतिरिक्त हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियाँ, ग्वादर, हंबनटोटा तथा अन्य बंदरगाहों का विकास, तथा तथाकथित "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स" रणनीति भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है (KSPP, 2026)। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने SAGAR, MAHASAGAR, नेबरहुड फर्स्ट, इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव, तथा Quad के माध्यम से समुद्री सहयोग, मानवीय सहायता, समुद्री निगरानी तथा क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ किया है।

वर्तमान प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के मध्य अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, 5G नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति शृंखला तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व को लेकर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इससे स्पष्ट है कि भारत–चीन संबंध बहुआयामी सामरिक प्रतिस्पर्धा के नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं।

8. समकालीन परिप्रेक्ष्य (2025–2026): दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका के नए आयाम

इक्कीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में दक्षिण एशिया की भू-राजनीति तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। चीन की भूमिका अब केवल अवसंरचनात्मक निवेश अथवा आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा, हरित ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला तथा वैश्विक व्यापारिक संपर्क जैसे नए क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुकी है। वर्ष 2025–2026 के दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट किया है कि दक्षिण एशिया अब केवल भारत और चीन के बीच पारंपरिक शक्ति-संघर्ष का क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक एवं सामरिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र बन चुका है (CKGSB Knowledge, 2026; Griffith Asia Institute, 2026)।

8.1 CPEC 2.0 और क्षेत्रीय संपर्क की नई दिशा

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का दूसरा चरण (CPEC 2.0) दक्षिण एशिया में चीन की बदलती रणनीति को स्पष्ट करता है। प्रारम्भिक चरण में जहाँ परिवहन, ऊर्जा तथा अवसंरचना निर्माण पर विशेष बल दिया गया था, वहीं वर्तमान चरण में औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, खनिज संसाधनों तथा औद्योगिक आपूर्ति शृंखलाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त चीन CPEC को अफ़ग़ानिस्तान तक विस्तारित करने की संभावना पर भी कार्य कर रहा है, जिससे मध्य एशिया, दक्षिण एशिया तथा पश्चिम एशिया के मध्य संपर्क को नई दिशा मिल सकती है (MP-IDSA, 2026; Al Jazeera, 2026)।

8.2 डिजिटल सिल्क रोड और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा

हाल के वर्षों में चीन ने डिजिटल सिल्क रोड (Digital Silk Road) के माध्यम से दक्षिण एशिया में दूरसंचार, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट शहर, डिजिटल भुगतान तथा ई-कॉमर्स अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। अनेक दक्षिण एशियाई देशों में चीनी कंपनियाँ 5G नेटवर्क, निगरानी प्रणालियों तथा डिजिटल अवसंरचना

परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे डिजिटल संपर्क और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला है, किन्तु डेटा सुरक्षा, साइबर संप्रभुता तथा डिजिटल निर्भरता को लेकर नई चिंताएँ भी उत्पन्न हुई हैं (CKGSB Knowledge, 2026)।

8.3 हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा

हिंद महासागर क्षेत्र चीन की समुद्री रणनीति का प्रमुख केंद्र बन चुका है। चीन का लगभग 30 प्रतिशत समुद्री व्यापार तथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा आयात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। परिणामस्वरूप चीन ग्वादर, हंबनटोटा तथा अन्य बंदरगाहों के माध्यम से अपनी समुद्री उपस्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। यद्यपि चीन इन परियोजनाओं को व्यावसायिक सहयोग का माध्यम बताता है, फिर भी अनेक रणनीतिक विश्लेषक इन अवसंरचनाओं की संभावित दोहरे उपयोग (Dual-use) क्षमता की ओर संकेत करते हैं (KSPP, 2026)। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने महासागर (MAHASAGAR) पहल, सागर (SAGAR), Quad, इंडो-पैसिफिक महासागरीय डोमेन जागरूकता (IPMDA) तथा विभिन्न द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। यह प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में हिंद महासागर को वैश्विक सामरिक राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बना सकती है (ORF, 2026)।

8.4 आपूर्ति शृंखलाएँ, दुर्लभ खनिज और हरित अर्थव्यवस्था

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में लिथियम, कोबाल्ट, निकल तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्व (Rare Earth Elements) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का महत्त्व निरंतर बढ़ रहा है। चीन इन संसाधनों के प्रसंस्करण, विनिर्माण तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अग्रणी भूमिका रखता है। दक्षिण एशिया में भी चीन ऊर्जा संक्रमण, विद्युत वाहन उद्योग, सौर ऊर्जा तथा हरित प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहा है। इससे क्षेत्रीय देशों को नई आर्थिक संभावनाएँ प्राप्त हुई हैं, किन्तु साथ ही आपूर्ति शृंखलाओं में अत्यधिक निर्भरता की आशंका भी बढ़ी है (Griffith Asia Institute, 2026)।

9. समालोचनात्मक विश्लेषण

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका का मूल्यांकन केवल सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक सहयोग, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सामरिक हित तथा क्षेत्रीय विकास सभी समान रूप से सम्मिलित हैं।

एक ओर चीन ने दक्षिण एशियाई देशों में अवसंरचना विकास की उस कमी को पूरा किया है जिसे लंबे समय तक अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थाएँ पूरा नहीं कर सकीं। पाकिस्तान में ऊर्जा परियोजनाओं, श्रीलंका में बंदरगाह विकास, बांग्लादेश में औद्योगिक निवेश तथा नेपाल में परिवहन अवसंरचना ने इन देशों की विकास क्षमता को सुदृढ़ किया है (Ammu & Ajitha, 2026)। दूसरी ओर कई परियोजनाओं में पारदर्शिता, वित्तीय व्यवहार्यता, पर्यावरणीय प्रभाव तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जुड़े प्रश्न भी सामने आए हैं। विशेष रूप से पाकिस्तान, मालदीव तथा श्रीलंका में ऋण पुनर्भुगतान और वित्तीय स्थिरता को लेकर अनेक चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। तथापि हाल के शोध यह भी संकेत देते हैं कि प्रत्येक देश के आर्थिक संकट के लिए केवल चीनी ऋण को उत्तरदायी ठहराना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि घरेलू आर्थिक नीतियाँ, वैश्विक वित्तीय बाजार तथा अन्य ऋणदाताओं की भूमिका भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण रही है (Georgetown Journal of International Affairs, 2021; CSIS, 2026)।

भू-राजनीतिक दृष्टि से चीन की नीति दक्षिण एशिया में भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय प्रधानता को चुनौती देती हुई दिखाई देती है। इसके परिणामस्वरूप भारत ने भी अपनी विदेश नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। नेबरहुड फर्स्ट, SAGAR, MAHASAGAR, Quad, IMEC तथा क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएँ इसी व्यापक रणनीतिक पुनर्संतुलन का हिस्सा हैं (ORF, 2026)। दक्षिण एशिया के छोटे एवं मध्यम आकार के राष्ट्रों की विदेश नीति भी उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हुई है। वर्तमान समय में अधिकांश देश किसी एक महाशक्ति के साथ पूर्ण संरेखण के बजाय बहु-संरेखण (Multi-

alignment) तथा सामरिक स्वायत्तता की नीति अपना रहे हैं। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश तथा मालदीव सभी चीन से आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हुए भारत, अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय देशों के साथ भी समानांतर संबंध बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया की समकालीन राजनीति में छोटे राष्ट्र भी सक्रिय रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं।

10.निष्कर्ष एवं नीति-सुझाव

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती हुई भूमिका इक्कीसवीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाओं में से एक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), बंदरगाह विकास, ऊर्जा अवसंरचना, डिजिटल संपर्क तथा औद्योगिक निवेश के माध्यम से चीन ने इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक एवं सामरिक उपस्थिति को अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ किया है। इन पहलों ने दक्षिण एशिया के अनेक देशों में आधारभूत संरचना, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक संपर्क तथा निवेश के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिली है (Ammu & Ajitha, 2026; Griffith Asia Institute, 2026)।

हालाँकि चीन की बढ़ती सक्रियता ने दक्षिण एशिया की पारंपरिक शक्ति-संरचना को भी प्रभावित किया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव तथा अफ़ग़ानिस्तान में चीन की गहरी होती आर्थिक एवं सामरिक भागीदारी ने भारत–चीन प्रतिस्पर्धा को नए आयाम प्रदान किए हैं। विशेष रूप से हिंद महासागर में बढ़ती समुद्री गतिविधियाँ, बंदरगाहों का विकास, डिजिटल अवसंरचना, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखलाएँ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकियाँ भविष्य की क्षेत्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित करेंगी (KSPP, 2026; ORF, 2026)।

इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि चीन की सभी परियोजनाओं को केवल "ऋण-जाल कूटनीति" के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। अनेक परियोजनाओं ने वास्तविक आर्थिक लाभ, ऊर्जा उत्पादन तथा संपर्क-सुविधाओं का विस्तार किया है, जबकि कुछ मामलों में ऋण निर्भरता, पारदर्शिता, परियोजना प्रबंधन तथा स्थानीय भागीदारी से संबंधित गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इसलिए प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन उसकी आर्थिक व्यवहार्यता, राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए (Georgetown Journal of International Affairs, 2021; CSIS, 2026)।

वर्तमान परिदृश्य यह संकेत देता है कि दक्षिण एशियाई देश अब किसी एक महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) तथा बहु-संरेखण (Multi-alignment) की नीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत, चीन, अमेरिका, जापान तथा अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ समानांतर सहयोग स्थापित करना क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति का प्रमुख आधार बनता जा रहा है। यह प्रवृत्ति दक्षिण एशिया में संतुलित शक्ति-संरचना तथा अधिक व्यावहारिक कूटनीति के विकास का संकेत देती है।

इन परिस्थितियों में भारत के लिए आवश्यक है कि वह नेबरहुड फर्स्ट, सागर (SAGAR), महासागर (MAHASAGAR), बिम्सटेक (BIMSTEC) तथा इंडो-पैसिफिक सहयोग जैसी पहलों को और अधिक प्रभावी बनाए, ताकि पड़ोसी देशों के साथ विकास, संपर्क एवं सुरक्षा सहयोग को संस्थागत रूप दिया जा सके। साथ ही, भारत को क्षेत्रीय अवसंरचना, डिजिटल कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा तथा आपूर्ति शृंखलाओं में निवेश बढ़ाकर अपनी विकास साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए (ORF, 2026)।

अंततः, दक्षिण एशिया का भविष्य केवल भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा से निर्धारित नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय देशों की नीतिगत क्षमता, सामरिक विवेक तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करेगा। यदि आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा सहयोग तथा रणनीतिक संतुलन के बीच समुचित सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तो दक्षिण एशिया न केवल एशिया बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भी अधिक स्थिर, समृद्ध और प्रभावशाली क्षेत्र के रूप में उभर सकता है।

संदर्भ सूची

1. Al Jazeera. (2026, May 26). *Pakistan and China reach "new broad consensus" on boosting ties*. https://www.aljazeera.com/economy/2026/5/26/pakistan-and-china-reach-new-broad-consensus-on-boosting-ties
2. Ammu, S., & Ajitha, S. (2026). *Exploring 11 years of China's Belt and Road Initiative: What makes it unique in shaping South Asia's future? SAGE Open*. https://doi.org/10.1177/29769442251405653
3. Asia Times. (2026, July 1). *CPEC gave Balochistan roads and power. CPEC 2.0 must deliver jobs*. https://asiatimes.com/2026/07/cpec-gave-balochistan-roads-and-power-cpec-2-0-must-deliver-jobs/
4. Center for Strategic and International Studies. (2026, March 17). *Game of loans: How China bought Hambantota*. https://www.csis.org/analysis/game-loans-how-china-bought-hambantota
5. China–Pakistan Economic Corridor Secretariat. (2026). *Official website*. Government of Pakistan. https://cpec.gov.pk/
6. CKGSB Knowledge. (2026, March 2). *China's Belt and Road enters a new phase*. https://english.ckgsb.edu.cn/knowledge/article/china-belt-and-road-enters-a-new-phase/
7. Daily Pakistan. (2026, May 26). *Pakistan, China push CPEC 2.0 forward with focus on connectivity, energy and investment*. https://en.dailypakistan.com.pk/26-May-2026/pakistan-china-push-cpec-2-0-forward-with-focus-on-connectivity-energy-and-investment
8. Development Watch Centre. (2025, February 12). *Damaging lies: Sri Lankan port deal with China not a debt trap*. https://www.dwcug.org/damaging-lies-sri-lankan-port-deal-with-china-not-a-debt-trap/
9. East Asia Forum. (2025, October 16). *China–Pakistan Economic Corridor relaunch exposes China–Pakistan interdependence*. https://eastasiaforum.org/2025/10/16/china-pakistan-economic-corridor-relaunch-exposes-china-pakistan-interdependence/
10. Eurasia Review. (2025, December 12). *Pakistan–Bangladesh–China strategic geometry in South Asia*. https://www.eurasiareview.com/
11. Fair Observer. (2025, October 27). *Bangladesh now aligns with China, India worries*. https://www.fairobserver.com/
12. Friends of Socialist China. (2026, June 6). *Sri Lanka's Hambantota port and the complete collapse of the debt trap narrative*. https://socialistchina.org/2026/06/06/sri-lankas-hambantota-port-and-the-complete-collapse-of-the-debt-trap-narrative/
13. Georgetown Journal of International Affairs. (2021, June 5). *Questioning the debt-trap diplomacy rhetoric surrounding Hambantota Port*. https://gjia.georgetown.edu/2021/06/05/questioning-the-debt-trap-diplomacy-rhetoric-surrounding-hambantota-port/
14. Griffith Asia Institute. (2026, January 18). *China Belt and Road Initiative investment report 2025*. Griffith University. https://blogs.griffith.edu.au/asiainsights/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2025-2/
15. Groundviews. (2025, September 1). *Sri Lanka, China and debt trap diplomacy*. https://groundviews.org/

16. Institute of South Asian Studies. (2026, February 11). *Structural ties, political change: Bangladesh, China and the next government*. National University of Singapore. https://www.isas.nus.edu.sg/

17. KSPP. (2026, February 3). *India's maritime strategy against China's String of Pearls*. Karnataka State Policy and Planning Commission. https://www.kspp.edu.in/

18. Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. (2026, April 9). *CPEC Phase II and China-linked supply chains in Pakistan*. https://idsa.in/

19. Observer Research Foundation. (2025, December 22). *The changing nature of China's engagement in the Maldives*. https://www.orfonline.org/

20. Observer Research Foundation. (2026, March 16). *Bangladesh's pivot to China: From balance to realignment*. https://www.orfonline.org/

21. Organisation for Research on China and Asia. (2022). *Maldives–China relations*. https://orcasia.org/

22. Rising Nepal Daily. (2025, January 12). *Nepal–China connectivity gains traction with BRI framework*. https://risingnepaldaily.com/

23. South Asian Voices. (2025, April 15). *Assessing China's growing footprint in Nepal*. https://southasianvoices.org/

Copyright & License:
© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.